

म्याँमार का सैन्य तख्तापलट

इस Editorial में The Hindu, The Indian Express, Business Line आदि में प्रकाशित लेखों का विश्लेषण किया गया है। इस लेख में म्याँमार में सैन्य तख्तापलट की हालिया घटना और भारत-म्याँमार संबंधों पर इसके प्रभावों व इससे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है। आवश्यकतानुसार, यथास्थान टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल किये गए हैं।

संदर्भ:

लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें राज्य का शासन चलाने में नागरिकों की पर्याप्त भागीदारी होती है और जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उनके लिये देश का शासन चलाते हैं।

हालाँकि विश्व के सभी हिस्सों में इस इस आदर्श वाक्य का पालन नहीं किया जा रहा है। इसका नवीनतम उदाहरण म्याँमार है जहाँ की सेना ने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को नज़रबंद करने के साथ ही देश में एक वर्ष के लिये आपातकाल की घोषणा करते हुए शासन को अपने हाथ में ले लिया।

इस कठिन परिस्थिति ने भारतीय विदेश नीति के समक्ष एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के कारण भारत को म्याँमार में लोकतंत्र का समर्थन करना होगा परंतु वर्तमान स्थिति में भारत को अपने सुरक्षा और विकास संबंधी हितों की भी रक्षा करनी होगी।

म्याँमार में तख्तापलट:

म्याँमार की सेना ने देश की स्वतंत्रता (वर्ष 1948) के बाद से तीसरी बार सरकार का तख्तापलट किया है।

- हालाँकि म्याँमार की सेना के अधिकारियों ने अपने बचाव में इसे तख्तापलट मानने से इनकार किया है।
- वर्तमान में शासन की सभी शक्तियों को कमांडर-इन-चीफ मनि आंग ह्लाइंग को स्थानांतरित करते हुए देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है।

म्याँमार की यातनापूर्ण राजनीति:

- **जुंटा का दोहरा मापदंड:**
 - वर्ष 2008 में म्याँमार की सेना द्वारा एक नागरिक पार्टी के माध्यम से सत्ता में बने रहने के उद्देश्य से देश का संविधान तैयार किया गया था।
 - वर्ष 2015 में यूनिफ़ॉर्म सॉलडियरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी (यूएसडीपी) चुनाव हार गई जिससे सेना को काफी नाराजा हुई क्योंकि सेना एक नए लोकतांत्रिक म्याँमार के उदय को लेकर चिंतित थी जो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (एनएलडी) की जीत के साथ उभर सकती थी।
- **रोहिंग्याओं के प्रति शत्रुता:** वर्ष 2020 के चुनाव के पहले सेना ने आतंकवाद से लड़ने के नाम पर देश के रखाइन राज्य में [रोहिंग्या समुदाय](#) के लोगों पर एक क्रूर कार्रवाई शुरू कर दी, जिसने म्याँमार से लगभग 700,000 से अधिक रोहिंग्या मुसलमानों को पड़ोसी देशों (मुख्य रूप से बांग्लादेश) में भागने के लिये विवश कर दिया।
- **नगण्य विदेशी हस्तक्षेप:** म्याँमार ने हमेशा ही किसी भी विदेशी या अंतरराष्ट्रीय शक्त को नगण्य हस्तक्षेप करने की अनुमति देते हुए स्वयं ही अपने आंतरिक संघर्षों से निपटने को प्राथमिकता दी है।
 - म्याँमार ने अपनी चुनौतियों पर रणनीति तैयार करने के लिये कुछ एशियाई और पश्चिमी देशों को शामिल कर स्थापित किये गए कई अंतरराष्ट्रीय तंत्रों को वर्ष 2015 के चुनाव के बाद भंग कर दिया था।
- **विभाजित म्याँमार समुदाय:** म्याँमार की सेना देश के लोगों की मानसिकता को अचूकी तरह से समझती है।
 - म्याँमार में बर्मान या बर्मार (बहुसंख्यक समूह) समुदाय और जातीय अल्पसंख्यकों के बीच व्यापक विभाजन है तथा आमतौर पर देश का अल्पसंख्यक समुदाय एक मज़बूत केंद्र सरकार के विरोध में होता है।
 - हालिया सैन्य तख्तापलट में बर्मान लोग [आंग सान सु की](#) के समर्थन में हैं, परंतु इस संदर्भ में उनका नरिणय बदल भी सकता है।
 - म्याँमार का बहुसंख्यक समुदाय बड़े पैमाने पर बौद्ध और शांतिप्रिय है। ऐसे में वे बगैर अधिक प्रतिरोध के इस सैन्य तख्तापलट को

स्वीकार भी कर सकते हैं।

म्याँमार संकट से जुड़े मुद्दों का सार:

- म्याँमार में नवंबर 2020 के चुनाव में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (एनएलडी) को एक शानदार वजिय प्राप्त हुई, इसमें उसने संघ, क्षेत्रीय और राज्य स्तर पर 82% संसदीय सीटों पर जीत हासिल की।
- सेना समर्थित यूनायिड सॉलडियरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी (यूएसडीपी) ने चुनावों में व्यापक धोखाधड़ी होने का दावा किया।
- सेना ने बगैर कोई ठोस सबूत प्रस्तुत किये ही वजियी पार्टी (एनएलडी) को सत्ता से हटा दिया और अधिकांश राजनीतिक नेताओं को हिरासत में ले लिया जिसमें म्याँमार सरकार की वास्तविक प्रमुख (de facto head) आंग सान सू की भी शामिल हैं।
- कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सैन्य तख्तापलट का वरिध करने के साथ प्रदर्शन करने के लिये सोशल मीडिया का प्रयोग किया।

वैश्विक प्रतिक्रिया:

- संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने म्याँमार में सैन्य तख्तापलट की "वफिलता" सुनिश्चित करने के लिये अंतरराष्ट्रीय समुदाय से पर्याप्त दबाव बनाने की बात कही है।
- चीन और रूस ने इस तख्तापलट के प्रतिकूल-मटोल वाला रवैया अपनाया है।
- [आसियान](#) (ASEAN) ने "बातचीत, सुलह और सामान्य स्थिति में लौटने के लिये एक मौन आह्वान किया, जबकि जापान ने इसे एक तख्तापलट कहा है।
- ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका सहित पश्चिमी देशों ने प्रतिक्रिया की धमकी के साथ कड़े बयान जारी किये हैं।
 - अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस सैन्य कार्रवाई को तख्तापलट के रूप में संदर्भित किया है और सेना से "हथियारों की शक्ति को त्यागने", हिरासत में लिये गए सभी अधिकारियों और अधिकांशों को रिहा करने, दूरसंचार पर लगे प्रतिक्रियाओं को हटाने और हिसा से बचने का आह्वान किया है।

Timeline: Key events in history of Myanmar

Year	Events
1948	Myanmar gains independence from British rule
1962	Military leader Ne Win stages a coup and rules the country through Junta
1988	Aung San Suu Kyi returns to her home country as pro-democracy protests erupt against junta
1989	Suu Kyi is put under house arrest
1990	The National League for Democracy (NLD) wins elections, but military refuses to hand over power
2010	A pro-junta party wins Myanmar's first elections in 20 years
2010	Suu Kyi is freed from detention
2012	Suu Kyi wins a by-election and takes her seat in Parliament
2015	NLD wins a sweeping victory in general elections
2020	Myanmar holds elections, with the NLD registering a landslide win
2021	Myanmar military takes control of the country

म्याँमार राजनीतिक संकट और भारत:

- **भारत का रुख:**
 - भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य के रूप में म्याँमार मुद्दे में शामिल हुआ है।
 - तख्तापलट के तुरंत बाद भारत ने म्याँमार की राजनीतिक स्थिति पर अपनी चिंता व्यक्त की थी और कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया तथा कानून के शासन को बरकरार रखा जाना चाहिये।
 - हालाँकि भारत ने म्याँमार के हालिया घटनाक्रम पर गहरी चिंता व्यक्त की है परंतु म्याँमार की सेना के साथ संबंधों को स्थगित करना एक व्यवहार्य विकल्प नहीं होगा क्योंकि म्याँमार और उसके पड़ोस के साथ भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक तथा सामरिक हित जुड़े हैं।

भारत के लिये म्याँमार का महत्व:

- **भारत-म्याँमार संबंध:** [भारत और म्याँमार](#) सांस्कृतिक और लोगों के आपसी घनिष्ठ संबंधों से जुड़े हैं, जो व्यापार, आर्थिक, सुरक्षा और रक्षा से संबंधित विनिमय तक विस्तारित हैं।
- **महामारी में म्याँमार को भारत द्वारा दी गई सहायता:** भारत ने म्याँमार को दवा, परीक्षण किट और टीके प्रदान कर COVID-19 महामारी से निपटने हेतु सहायता उपलब्ध कराई है।
 - भारत ने इस महामारी के स्वास्थ्य और आर्थिक क्षेत्र से जुड़े दुष्प्रभावों को कम करने हेतु म्याँमार के लोगों के लिये अपने मानवीय समर्थन को जारी रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

- भारत द्वारा इस महामारी से लड़ने में म्याँमार को सहायता देने हेतु कोवशील्ड वैक्सीन की 15 लाख खुराक भी उपलब्ध कराई गई है।
 - म्याँमार ने भारत द्वारा भेजी गई COVID-19 वैक्सीन से टीकाकरण का कार्य शुरू कर दिया है, जबकि उसने अभी चीन द्वारा भेजी गई 300,000 खुराक को रोककर रखा है।
- **पनडुबबी उपहार:** भारत ने किलो-वर्ग (Kilo class) की पनडुबबी आईएनएस सधिवीर (UMS Minye Theinkhathu) म्याँमार नौसेना को सौंपी है।
 - भारत द्वारा उपहार स्वरूप दी गई यह पनडुबबी म्याँमार नौसेना की पहली और एकमात्र पनडुबबी है।
- **वदिश नीति:** म्याँमार के लिये भारत की सैन्य-राजनयिक आउटरीच एक्ट ईस्ट नीति की आधारशिला बन गई है।
 - पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को वदिरोही समूहों से सुरक्षा करने में म्याँमार सेना की सहायता तथा अन्य मामलों में द्वपिकषीय सहयोग के कारण म्याँमार की सेना के साथ भारत के सुरक्षा संबंध अत्यंत घनषिठ हो गए हैं। ऐसे में कोई भी ऐसा कदम उठाना भारत के लिये बहुत कठिन होगा जिनकी इन उपलब्धियों के वरिद्ध जाने की संभावना हो।
- **आधारभूत संरचना और वकिसात्तमक परयोजनाएँ:** रणनीतिक हितों के अलावा भारत ने म्याँमार के साथ कई बुनियादी ढाँचे और वकिसा परयोजनाओं पर भी कार्य किया है, जैसे वह आसियान देशों तथा "पूर्व के प्रवेश द्वार"के रूप में देखता है।
 - इनमें भारत-म्याँमार-थाईलैंड त्रपिकषीय राजमार्ग और कलादान मल्टी-मोडल ट्रांज़िट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के साथ सतिवे बंदरगाह (Sittwe Port) पर एक वशिष आर्थिक कषेत्र की योजना शामिल है।

आगे की राह:

- **वभिन्न समुदायों के बीच अंतर को कम करना:** म्याँमार के लोगों के बीच सांप्रदायिक वभिजन को देखते हुए इस नषिकर्ष पर पहुँचना कि म्याँमार में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ देशव्यापी वरिध प्रदर्शन देखने को मलैगा, सही नहीं है।
 - वर्तमान परदृश्य में सेना जातीय और धार्मिक वभिजन का दोहन करना जारी रखेगी।
 - अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा जातीय अल्पसंख्यकों (वशिष रूप से देश के उत्तरी भाग से) सहति घरेलू हतिधारकों के साथ संपर्क स्थापति करने का प्रयास किया जाना चाहिये।
- **प्रतबिधों की धमकी देना समाधान नहीं है:** अतीत में भी म्याँमार की सेना हमेशा ही एशियाई देशों के साथ समझौतों के माध्यम से आर्थिक रूप से प्रतबिधों का मुकाबला करने में सक्षम रही है, ऐसे में म्याँमार पर प्रतबिध लगाकर किसी बड़े राजनीतिक परिवर्तन की उम्मीद करना सही नहीं होगा।
- **सेना की आलोचना करने से बचना:** भारत कई कारणों से म्याँमार में अवश्य ही बने रहना चाहेगा।
 - कई उग्रवादी समूह म्याँमार में आश्रय प्राप्त करते हैं, जिसका अर्थ है कि भारत को उनका मुकाबला करने के लिये म्याँमार की सहायता की आवश्यकता है।
 - भारत के लिये म्याँमार के साथ जुड़ाव महत्त्वपूर्ण है, ऐसे में इसे म्याँमार के मामलों में सेना की प्रधानता को स्वीकार करते हुए दोतरफा जुड़ाव बनाए रखना होगा।

नषिकर्ष:

- **एक ऐसा देश जहाँ सैन्य नेतृत्व ने अपने शब्दों में लोकतंत्र की परभिषा गढ़ी हो वहाँ तनाव की संभावना बहुत प्रबल होगी।**
 - ऐसे मामलों में घरेलू सेनाएँ और भू-राजनीति अकसर इस प्रकार के तंत्र के कार्यों और उसके शासन करने के आवेग को रोकने में वफिल होती हैं।
- **किसी देश में लोकतंत्र को खतरा होने पर भारत का चतिति होना स्वाभाविक है।**
 - परंतु भारत को वर्तमान में दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की अपनी नीति के प्रतबिध रहना चाहिये।
 - भारत को अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अपने सदिधांतों, मूल्यों, रुचियों और भू-राजनीतिक वास्तवकिताओं को सूक्ष्मता से संतुलित करना होगा।

अभ्यास प्रश्न: म्याँमार में सैन्य तख्तापलट की हालिया घटना की समीक्षा करते हुए भारत-म्याँमार संबंधों पर इसके प्रभावों की चर्चा कीजिये।